सन्मार्ग
गुरुवार ॥ 24 अगस्त, 2017 ॥ कोलकाता

जीएसटी पर मर्चेंट चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की कार्यशाला में बोले विशेषज्ञ

जीएसटी अच्छा, पर अभी समस्याएं बहुत हैं

सन्मार्ग संवाददाता, कोलकाता: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कारोबार के लिहाज से अच्छा है और लंबे समय में इसके बहुत लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में यह छोटे व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। उनके सामने इतनी औपचारिकताएं आ गई हैं कि वे पूरी ही नहीं कर पा रहे। यह बात मर्चेंट चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 'जीएसटी अनुपालन में चुनौतियां और भविष्य' विषय पर आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कहीं।

केपीएमजी इन-डायरेक्ट टैक्स के सहायक निदेशक अभिषेक मिश्रा, आदित्य हंस और संजीब कोठारी ने कहा कि जीएसटी में सुधार की जरूरत है। इसके लिए सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पेशेवर को भी बहुत-सी बातें स्पष्ट नहीं हैं। अपंजीकृत विक्रेता राज्य के बाहर है, इससे खरीदे गये माल पर इनपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं, इस पर टैक्स जमा करें या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। रिटर्न फाइल में परेशानी हुई है। सितंबर महीने में 5-6 एक साथ रिटर्न फाइल करना है। कम समय में बहुत सारे अनुपालन करने हैं। बहुत सारी अस्पष्टता की वजह से अनुपालन करने में परेशानी हो रही है। जैसे-शेयर का मुआवजा। जीएसटी फार्म में अस्पष्टता है उसमें सुधार की आवश्यकता है। जब तक स्पष्टता नहीं आती, तब तक उस पर कर दिया जाए।

प्रभात खबर

कोलकाता, गुरुवार

24.08.2017

एमसीसीआइ का जीएसटी पर सेमिनार

कोलकाता. बुधवार को मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जीएसटी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सेमिनार को संबोधित करते हुए इंडियन टैक्स केपीएमजी के एसोसिएट डॉयरेक्टर

अभिषेक मिश्रा और टैक्स सर्विस केपीएमजी के पार्टनर आदित्य हंस ने उपस्थित लोगों को टैक्स के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी टैक्स एक बेहतरीन टैक्स व्यवस्था है, जिसके लागू होने से पूरे देश में टैक्स सिस्टम में एकरूपता आयेगी. कार्यक्रम में दोनों वक्ताओं ने जीएसटी टैक्स के बारे में बताया. कार्यक्रम के अंत के बाद जीएसटी विशेषज्ञ अभिषेक मिश्रा और आदित्य हंस ने उपस्थित लोगों के प्रश्नों का जबाब भी दिया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एमसीसीआइ के पदाधिकारियों व सदस्य उपस्थित रहे.

सलाम दुनिया

कोलकाता, 24 अगस्त 2017, गुरुवार

एमसीसीआई में जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित

संवाददाता, सलाम दुनिया

कोलकाता : मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) की तरफ से जीएसटी पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में केपीएमजी के कर सेवाओं के सहभागी आदित्य हंस और केपीएमजी के एसोसिएट निदेशक, अभिषेक मिश्रा उपस्थित थे। इसके अलावा संजीव कोठारी, एम.सी दास व विभिन्न उद्योगों से संबंधित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। कार्यशाला के दौरान आदित्य हंस ने कहा कि देश में जीएसटी को लागू हुए 50 दिन हो चुके हैं लेकिन क्या हमने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है, नहीं न।

हमने दूसरे रास्ते तलाशे हैं। अभी तक तो जीएसटी काफी अच्छी तरह से चला लेकिन अब जब लोग इसका वास्तविक रूप से उपयोग कर रहे हैं, तो कई तरह की समस्याएँ सामने आ रही हैं जिन पर सरकार ध्यान अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि नि:संदेह यह बहुत अच्छा कानून है, ऐसा नहीं है कि इस कानून के रास्ते में जो समस्याएँ आ रही हैं उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है।

हंस ने कहा कि अगर सरकार ने 2-3 सप्ताह इस पर ध्यान दे दिया तो इन समस्याओं को आसानी से दूर कर इसे और बेहतर किया जा सकता है। कार्यशाला के दौरान आदित्य ने कहा कि समाज के किस श्रेणी में उत्पादों की कितनी खपत होती है, इसको ध्यान में रखकर ही जीएसटी में 7 तरह का टैक्स स्लैब रखा गया है। इस दौरान जीएसटी से संबंधित दूसरी समस्याओं और उनके समाधान पर भी विचार किया गया। ●

BUSINESS ECONOMICS | August 16-31, 2017

MCCI

Repo rate cut by the RBI hailed

Hemant Bangur, President, Merchants' Chamber of Commerce & Industry (MCCI), has hailed the decision to cut the repo rate by 25 basis points to year low of 6% by the Reserve Bank of India (RBI). He feels that this move will go on to improve the overall economic prospects of the country. The cut in the key lending rate is expected to make loans cheaper, boost borrower sentiments, augment investment flows, and help in economic expansion, feels the MCCI. The decision has been in line with objective of medium-term consumer inflation (CPI) target of 4% within a band of +/- 2%, which while supporting growth, will help the Indian economy's growth. This growth rate has been predicted to increase by 7.4% in FY 2017-18 and by 7.6% in FY 2018-19 on the back of an improving business environment created by reforms like the Goods and Services Tax (GST).

This expansionary Monetary Policy move will give a push to credit growth which has been sluggish from the last many quarters, will boost industrial growth which has remained weak; and the Chamber feels that this rate cut was extremely important since factory output slumped to 1.7% in May, from 8% a year ago due to poor performance of mining and manufacturing. ■ *BE Bureau*